

सरदार पटेल

भारत की राजनीतिक एकता के वास्तुकार

31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में एक किसान परिवार में पैदा हुए सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की आजादी की यात्रा में एक अहम व्यक्तित्व और इसके एकीकरण के वास्तुकार थे। उनके पिता झावेरभाई, एक देशभक्त किसान थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और उनकी माँ लाडबाई, एक गहरी धार्मिक आस्था और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थीं। दोनों ने वल्लभभाई में आत्मनिर्भरता, अनुशासन और सशक्त क्षमताओं के मूल्यों को स्थापित किया।

17 वर्ष तक अपने गाँव में ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1897 में नडियाड हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हुए, लेकिन शुरुआती दिनों में विश्वविद्यालय की शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण, उन्होंने एक जिला वकील के रूप में शुरुआत की। वर्ष 1910 में, वह मिडिल टेम्पल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने रोमन कानून में उत्कृष्टता प्राप्त की और 1912 में विशिष्टता के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1913 में भारत लौटने पर, उन्होंने अहमदाबाद में सफलता के साथ वकालत शुरू की, लेकिन धीरे-धीरे वे सार्वजनिक सेवा में शामिल होते चले गए।

सरदार पटेल के राजनैतिक सफर की शुरुआत खेड़ा सत्याग्रह (1918) के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़ने से हुई। उन्होंने अकाल के चलते आई मुश्किलों के कारण, करों का भुगतान करने से इनकार करने वाले किसानों का नेतृत्व किया, जो औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ उनकी पहली बड़ी जीत थी। इस अनुभव ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। बारडोली सत्याग्रह (1928) के दौरान अन्यायपूर्ण कर वृद्धि के खिलाफ उनके नेतृत्व ने उन्हें "सरदार" की उपाधि दी, जो एक जननेता के रूप में उनकी भूमिका की पहचान थी।

पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई, असहयोग आंदोलन में भाग लिया और दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कारावास में वक्त बिताना पड़ा। गांधीजी के भरोसेमंद साथी के रूप में उन्होंने कांग्रेस के कराची सत्र (1931) की अध्यक्षता की और भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठनात्मक प्रयासों का नेतृत्व किया।

स्वतंत्रता के बाद, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में, पटेल ने अपनी सबसे यादगार उपलब्धि हासिल की: 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण। भारी चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने कूटनीति और दृढ़ता के ज़रिए संपूर्ण देश को एकजुट किया और "भारत के लौह पुरुष" की उपाधि प्राप्त की। उनके कार्यों ने एक लोकतांत्रिक और संप्रभु भारत के लिए एक स्थिर आधार सुनिश्चित किया। पटेल ने संविधान को तैयार करने और प्रशासनिक ढांचे की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई।

15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया और वे "भारत के एकीकरणकर्ता" के रूप में एक अमिट विरासत छोड़ गए। उन्हें विश्व स्तर पर श्रद्धांजलि दी गई, प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें " साहस की इमारत" और

"आधुनिक भारत का निर्माता" कहकर संबोधित किया। उनका योगदान भारत की एकता और लोकतांत्रिक लोकाचार की आधारशिला बना हुआ है।

संविधान सभा में सरदार पटेल द्वारा दिये गये भाषणों के अंश

राज्यों के एकीकरण पर

"केंद्र सरकार को प्रांतों की तरह राज्यों में भी समान कार्य करने चाहिए और समान शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए"

"500 से अधिक राज्यों को बड़ी इकाइयों में एकीकृत करके और सदियों पुरानी निरंकुशता को पूरी तरह समाप्त करके भारतीय लोकतंत्र ने एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस पर भारत के राजाओं और जनता को समान रूप से गर्व होना चाहिए। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसका श्रेय इतिहास के किसी भी चरण में, किसी भी राष्ट्र या लोगों को मिलना चाहिए।"

"राज्यों पर लागू संविधान के प्रावधानों के संबंध में, अब जो संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वे उस रक्तहीन क्रांति के नतीजों को दर्शाते हैं, जिसने बहुत ही कम समय में राज्यों के आंतरिक और बाहरी ढांचे को बदल कर रख दिया है।"

"भले ही अनुच्छेद, प्रभावित राज्य की विधायिका के परामर्श या सहमति का प्रावधान प्रदान करता है, जनता की इच्छाओं को केंद्र सरकार या विधायिका द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

"दिसंबर 1947 से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राज्यों के एकीकरण और लोकतंत्रीकरण की नीति के परिणामस्वरूप, राज्यों के 'संघीकरण' के रूप में वर्णित की जाने वाली प्रक्रिया में काफी तेजी आई है।"

एकीकृत संविधान के महत्व पर

"हमने विभिन्न संघों के प्रधानमंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा की और उनकी सहमति से निर्णय लिया कि राज्यों का संविधान भी भारत के संविधान का अभिन्न अंग होना चाहिए।"

"राज्यों के संबंध में संघ का विधायी और कार्यकारी प्राधिकार, प्रांतों में और उनके ऊपर अपने समान प्राधिकार के साथ सह-विस्तारित होगा।"

"हमारा नया संविधान लोकतंत्रों और राजवंशों के बीच गठबंधन नहीं है, बल्कि लोगों की संप्रभुता की मूल अवधारणा पर निर्मित भारतीय जनता का वास्तविक संघ है।"

राज्यों के एकीकरण के लाभों पर

"राज्यों को एकीकरण की प्रक्रिया से काफी लाभ हुआ है, खासकर शासकों से विरासत में मिली नकदी के रूप में।"

"प्रिंसीपल समझौता, शासकों द्वारा अपनी सभी सत्तारूढ़ शक्तियों के समर्पण और अलग इकाइयों के रूप में राज्यों के विघटन पर विचार करने की प्रकृति में है।"

“राज्यों में निरंकुशता खत्म हो गई है और ऐसा सभी के हित के लिए ही हुआ है”

लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज्य

“पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता, जो कांग्रेस का उद्देश्य है, राज्यों सहित पूरे भारत के लिए है, क्योंकि भारत की अखंडता और एकता को स्वतंत्रता में बनाए रखा जाना चाहिए, जैसा कि इसे अधीनता में बनाए रखा गया है।”

“कांग्रेस के लिए एकमात्र प्रकार का संघ वही हो सकता है, जिसमें राज्य स्वतंत्र इकाइयों के रूप में भाग लेते हैं और शेष भारत की तरह ही लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं।”

“जिस रक्तहीन क्रांति की वजह से लाखों लोगों की नियति बदल गई है, हमें उसकी कीमत को कम करके नहीं आंकना चाहिए।”

भारत के एकीकरण पर

“भारत का राजकोषीय एकीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था में विघटनकारी प्रभावों को ठीक करेगा, जिसकी वजह से प्रांतों में आर्थिक नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन असंभव हो गया था।”

“भारत सरकार ने विलय और एकीकृत राज्यों के शासकों को विलय के विभिन्न प्रावधानों और समझौतों की शर्तों के तहत, तय किए गए प्रिवी पर्स के भुगतान की गारंटी दी है।”

“हमारा नया संविधान लोकतंत्रों और राजवंशों के बीच का गठबंधन नहीं है, बल्कि लोगों की संप्रभुता की मूल अवधारणा पर निर्मित भारतीय लोगों का वास्तविक संघ है।”

“यह राज्यों के लोगों और प्रांतों के लोगों के बीच सभी बाधाओं को दूर करता है और पहली बार, सहकारी उद्यम की सच्ची नींव पर निर्मित प्रांतों और राज्यों के लोगों की ओर से एक मजबूत लोकतांत्रिक भारत के उद्देश्य को प्राप्त करता है।”

“भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे राज्यों या प्रांतों में रहते हों, उन्हें समान मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे और उन अधिकारों को लागू करने के लिए समान कानूनी प्रक्रिया भी प्राप्त होंगी।”

“आखिरकार हम एक लोकतंत्र हैं, जिसकी नींव जनता की इच्छा पर टिकी है और हम जनता की राय की उपेक्षा करके कार्य नहीं कर सकते।”